यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/91/2017 **दिनांक :** 12.10.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

यूएफबीयू की बैठक

युनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स की एक बैठक 02.10.2017 को मुम्बई में सम्पन्न हुई। इस विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपना परिपत्र संख्या 28/30/2017/30 दिनांक 10.10.2017 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

02.10.2017 को हुई यूएफबीयू की बैठक

यूएफबीयू परिपत्र का प्रलेख : ' यूएफबीयू की एक बैठक 02.10.2017 को मुम्बई में आयोजित की गई थी। साथी के.के नायर, अध्यक्ष, यूएफबीयू ने बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक ने मुम्बई में एल्फिन्स्टन रेलवे स्टेशन ब्रिज पर फुट ओवर ब्रिज में भगदड़ में निर्दोष लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए एक मिनट का मौन धारण किया।

वेतन पुनरीक्षण मुद्दा : बैठक में वेतन पुनरीक्षण तथा सेवा शर्तों में सुधार पर हमारे द्वारा प्रस्तुत माँग पत्र पर कामगार यूनियनों एवं अधिकारी संगठनों तथा आईबीए के मध्य अब तक हुए विचार विमर्श पर पूरी रिपोर्टिंग हुई।

बैठक ने नोट किया कि जबकि अब तक इन चर्चाओं के दौरान कुछ गैर–वित्तीय माँगें और मुद्दे विचार–विमर्श के लिए उठाये गये हैं, वेतन में वृद्धि के मुख्य मुद्दे को अब भी आईबीए के साथ निपटाया जाना है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि आईबीए को प्रभावित किया जाना चाहिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जल्द से जल्द पूर्ण नेगोशिएटिंग कमेटी की बैठक आयोजित करने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। यह निर्णय भी लिया गया कि आईबीए को राजी किया जाये कि महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि संशोधित वेतनमान का निर्माण, सूचकांक बिन्दु जहां तक महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ विलय किया जाना है, भत्तों में संशोधन तथा अन्य वित्तीय माँगों पर विचार–विमर्श में भी शीघ्रता की जाये।

जारी पृष्ठ 2

अधिकार पत्र : बैठक ने चिंता के साथ यह भी नोट किया कि आईबीए अभी भी केवल स्केल III अधिकारियों तक अधिकारी संगठनों के साथ वार्ता सीमित करने की अपनी शर्त पर जोर दे रही थी और इस मामले को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

समूह चिकित्सा बीमा योजना पर विचार विमर्श : बैठक ने नोट किया कि यूएफबीयू की माँग की प्रतिक्रिया में, आईबीए ने योजना के कार्यान्वयन में सामना की जाने वाली समस्याओं पर यूएफबीयू द्वारा उठाये गये मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और इसमें सुधार के प्रयास करने के लिए यूआईआईसी तथा सभी टीपीए के साथ 06.10.2017 को एक बैठक बुलाई थी। (06.10.2017 को हुए विचार विमर्श का विवरण अगले परिपत्र में यूनियनों को सूचित किया जायेगा)।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर हमले – हमारे आन्दोलन को तेज करने की आवश्यकता है : बैठक ने 22.08.2017 की हड़ताल की भारी सफलता के लिए हमारी सभी यूनियनों की सम्पूर्ण सदस्यता को बधाई दी। हालांकि, बैठक ने नोट करते हुए खेद व्यक्त किया कि सरकार बैंकिंग सुधारों की अपनी कार्यसूची को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक थी और बैंकों के विलय पर मंत्रिमण्डल की मंजूरी ली गई है। इस पृष्ठभूमि में, यह देखा गया कि 15.09.2017 को एआईबीईए, आईबौक, एनसीबीई, एआईबीओए, बैफी, इन्बैफ तथा इन्बौक द्वारा आयोजित संसद पर मोर्चा हमारे सदस्यों द्वारा बड़ी भागीदारी के साथ एक बड़ी सफलता बन गया।

बैठक में 15.09.2017 को हुई बैठक के दौरान वित्त मंत्री को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन पर उनके साथ हुए विचार विमर्श को भी रिपोर्ट किया गया था।

सुधार नीतियों को तेज करने के सरकार के निरन्तर प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि हड़ताल और मोर्चा में उठाई गई माँगों को विभिन्न अभियानों और आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सख्ती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और 2 दिवसीय हड़ताल करने के निर्णय को भी दोहराया गया। कार्यक्रमों को हमारे अगले परिपत्र में शीघ्र ही सूचित किया जायेगा।

यूएफआरआरबीयू की माँगों और 10 और 11 दिसम्बर 2017 की उनकी हड़ताल को समर्थन : बैठक ने उनकी माँगों और 10 और 11 दिसम्बर, 2017 की प्रस्तावित हड़ताल का समर्थन करने के लिए युनाईटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियन्स से प्राप्त पत्र पर चर्चा की। चूंकि उनकी न्यायोचित मांगें जैसे सेवा शर्तों में समानता, न्यायोचित मांगों से इंकार और आरआरबी के निजीकरण के विरूद्ध उनके प्रतिरोध में उनके द्वारा आगे बढ़ाये जा रहे हैं, उनको और उनके कार्यक्रमों को हमारे समर्थन देने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि मांगों को सौहार्दपूर्ण तरीके और शीघ्रता से हल करने के लिए इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र लिखे जायें।'

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री